हल्द्वानी (नैनीताल) एवं देहरादून से एक साथ प्रकाशित

समाचारों को विस्तार से व तत्काल पढ़ने के लिए क्लिक करें
Web:- www.jokhimnews.com
सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में "ए" श्रेणी में सूचीबद्ध

जोखिम

भय भूख एवम् भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत् निर्भीक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

वर्ष : 16 अंक : 84 | हल्द्वानी (नैनीताल) बुधवार 04 फरवरी 2026 | मूल्य रू 2 | पृष्ठ : 8

हिमांशु ठाकुर पर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मुकदमा पिछले 24 घंटे से काफी सुर्खियों में

काशीपुर संवाददाता. शोसल मीडिया पत्रकार हिमांशु ठाकुर पर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मुकदमा पिछले 24 घंटे से काफी सुर्खियों में हैं,इसकी एक वजह है कि जिसने मुकदमा लिखवाया है,फोन भी उसी ने किया और

पैसा देने की पैशकश भी उसी ने की है, जबकि जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, उनसे एक बार भी पैसे का जिक्र तक नहीं किया है, फिर मुकदमा उस मित्र पुलिस ने दर्ज किया है,जो रंगदारी के मामले में पिछले दिनों खुद पत्रकारों को मैनेज करती घूम रही थी,ताकि साहब की कुर्सी बच जाए। जरुरत पड़ी तो इसके सबूत खबरों के माध्यम से दिखाए जायेंगे।आत्महत्या से पहले सुखवंत ने क्या कुछ नहीं कहा था,उसकी आडियो इसकी गवाह और सबूत दोनों है।इध र काशीपुर के शोसल मीडिया पत्रकार की जिस आडियो रिकार्डिंग को सबूत मानकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है,उसकी सच्चाई सबसे समाने है। महिला खुद पत्रकार को फोन करती है, आडियो में यह बात महिला ने खुद कबूल भी की है, फिर पैसा देने की बात कर रही है,जबिक पत्रकार ने एक बार भी पैसे को लेकर कोई भी बात नहीं की है,जबकि उसी महिला पर पूर्व एक व्यक्ति से रंगदारी का आरोप कैमरे पर एक पीड़ित ने लगाए हैं,जिसकी खबर हिमांशु ठाकुर ने प्रकाशित की है,उस महिला के खिलाफ ईमानदार पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है,और उसी महिला द्वारा सच्चाई को उजागर करने वाले पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

अधिशासी निदेशक की तैनाती को लेकर यूकेडी ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

डोईवाला संवाददाता। यूकेडी ने उपजिलाधिकारी डोईवाला के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी निदेशक की तैनाती की तुरंत मांग की है। यूकेडी नेता केंद्रपाल सिंह तोपवाल ने बताया कि 17 जनवरी को शुगर मिल डोईवाला में नए अधिशासी निदेशक की नियुक्ति की गई थी मगर एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी उन्होंने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है जिससे गन्ना किसको को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा

कि अधिशासी निदेशक अगर जल्द ही अपना पदभार ग्रहण नहीं करती तो यूकेडी आंदोलन करने को बाध्य होगी। ज्ञापन देने वालों में केंद्रपाल सिंह तोपवाल, पवन विजलवान, धर्मपाल सिंह राणा, मदन सिंह बिष्ट, प्रताप सिंह बिष्ट आदि रहे।

एक महिला पति को छोड़ आठ साल की बेटी और 20 साल की युवती के साथ लापता

हल्द्वानी संवाददाता.। शहर क्षेत्र की एक महिला पति को छोड़ आठ साल की बेटी और 20 साल की युवती के साथ लापता है। पुलिस को महिला की लोकेशन. पंजाब में दिखाई दे रही है। दोनों परिवारों ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। महिला के पति ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी पत्नी बेटी के साथ 24 जनवरी को बिना किसी को बताए घर से चली गई। वहीं युवती के पिता ने कहा कि उनकी 20 वर्षीय बेटी 24 जनवरी को आफिस में काम करने के लिए घर से निकली, लेकिन फिर नहीं लौटी। पुलिस की मानें तो युवती व महिला के बीच प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि पुलिस तीनों की तलाश में जुटी है

दो दुकानदारों के बीच मामूली सी बात के बाद जबरदस्त विवाद

लालकुआं संवाददाता. यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के समीप स्थित दो दुकानदारों के बीच मामूली सी बात के बाद जबरदस्त विवाद हो गया, मौके पर एकत्रित कुछ युवकों ने एक दुकानदार एवं उसके कर्मचारी की

पिटाई लगा दी, आसपास के अन्य दुकानदारों ने दोनों को बमुश्किल उक्त युवकों के चुंगल से बचाते हुए सुरक्षित स्थान में पहुंचाया। इस दौरान भारी संख्या में एकत्रित युवक आक्रोशित हो गए,तथा दुकान में तोड़फोड़ करने पर आमादा हो गए, आसपास के अन्य दुकानदारों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया, इसके बाद दोनों पक्ष लालकुआं कोतवाली पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने उक्त आरोप को झूठा करार देते हुए बेवजह मारपीट करने की बात कही है। समाचार जारी होने तक देर रात दोनों पक्ष लालकुआं कोतवाली में एकत्रित थे।

भीमताल क्षेत्र में वन्यजीव हमले की एक दर्दनाक घटना सामने आई

नैनीताल संवाददाता. उत्तराखण्ड के नैनीताल जनपद अंतर्गत भीमताल क्षेत्र में वन्यजीव हमले की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। घास काटने जंगल गई 60 वर्षीय महिला पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी

मौके पर ही मौत हो गई। महिला का शव शनिवर सुबह जून स्टेट के जंगल से बरामद किया गया।स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतका गंगा देवी प्रतिदिन की तरह मवेशियों के लिए चारा लाने जून स्टेट से लगे जंगल में गई थीं। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से जंगल में खोज अभियान चलाया, लेकिन रात होने तक कोई सुराग नहीं मिल सका।शनिवार सुबह खोज के दौरान गंगा देवी का शव उनके घर से लगभग तीन किलोमीटर दूर जंगल में मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ी टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे और नियमित गश्त बढ़ाई जाएगी। साथ ही पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।वहीं, स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जंगली जानवरों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने आदमखोर वन्यजीव को काबू में करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।गौरतलब है कि हाल के दिनों में इस पहाड़ी क्षेत्र में वन्यजीवों के हमले की तीन जानलेवा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

राष्ट्रीय हड़ताल पर संयुक्त प्रदर्शन करेंगी यूनियनें

हल्द्वानी संवाददाता.12 फरवरी को खराष्ट्रीय हड़ताल को लेकर विभिन्न संगठनों ने बैठक की। इस दौरान संयुक्त प्रदर्शन का निर्णय लिया है। मंगलवार को हल्द्वानी में हुई बैठक में वक्ताओं ने चारों श्रमिक विरोधी लेबर कोड रद्द करने की मांग उठाई। 12 फरवरी की राष्ट्रीय हड़ताल के दिन बुध पार्क हल्द्वानी में विभिन्न संगठन संयुक्त रूप से प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान ऐक्टू के राष्ट्रीय सचिव केके बोरा, बीमा कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष हिमांशु चौधरी, ऐक्टू जिलाध्यक्ष जोगेंद्र लाल, आशा यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष रिंकी जोशी, भोजनमाता संगठन महामंत्री रजनी जोशी, माले जिला सचिव डॉ कैलाश पाण्डेय, पछास के चन्दन, महेश, आशा यूनियन उपाध्यक्ष रीना बाला, सरोज रावत, आकाश भारती आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय हड़ताल पर संयुक्त प्रदर्शन करेंगी यूनियनें

हल्द्वानी संवाददाता. 12 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल को लेकर विभिन्न संगठनों ने बैठक की। इस दौरान संयुक्त प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को हल्द्वानी में हुई बैठक में वक्ताओं ने चारों श्रमिक विरोधी लेबर कोड रद्द करने की मांग उठाई। साथ हीख 12 फरवरी की राष्ट्रीय हड़ताल के दिन बुधपार्क हल्द्वानी में होगा संयुक्त प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

हिन्दी दैनिक जोखिम

सम्पादकीय

चीन के साथ भारत का रिश्ता नफरत और जरुरत का

नफरत और प्यार का रिश्ता बहुत सुना गया होगा लेकिन चीन के साथ भारत का रिश्ता नफरत और जरुरत का है। चीन से नफरत भी है और उसकी जरुरत भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांध ी के चीन के राजदूत से मिलने की घटना को आसमान टूट पड़ने जैसी घटना माना था। उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही ठहराया गया। कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के साथ एक एमओयू साइन हुआ था, जिसे लेकर भाजपा ने बड़ा नैरेटिव खड़ा किया। लेकिन अब खुद भाजपा नेता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मिले हैं। भाजपा के विदेश प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विजय चौथाईवाला ने यह मुलाकात तय कराई और पार्टी मुख्यालय में महासचिव अरुण सिंह के साथ दूसरे नेता सीपीसी के प्रतिनिधिमंडल से मिले।

भाजपा के नेता यह कह कर फेस सेविंग कर रहे हैं कि चीन के डेलिगेशन से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन नहीं मिले या पार्टी के दोनों सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मुलाकात नहीं की, जबकि कांग्रेस में खुद राहुल गांधी मिले थे। लेकिन यह बचाव का तर्क नही हो सकता है। जैसे ही भाजपा नेताओं से सीपीसी डिलेगेशन के मिलने की तस्वीरें सामने आईं वैसे ही सन्नाटा खींच गया। सोशल मीडिया में भाजपा का पूरा इकोसिस्टम खामोश हो गया। इस बीच दो चार लोगों ने हिम्मत करके सवाल उठाया और दबी जुबान में कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ। भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद सीपीसी का डेलिगेशन आरएसएस कार्यालय में संघ के नंबर दो पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबाले से मिला। हालांकि उसकी फोटो नहीं जारी की गई। बाद में भारत की तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों से सीपीसी के प्रतिनिधिमंडल के मिलने की खबर भी आई।

अब सवाल है कि जिस समय चीन अरुणाचल प्रदेश में जन्मे भारतीय मूल के लोगों को अपने हवाईअड्डों पर रोक कर पासपोर्ट अवैध बता रहा है या अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताने वाले यूट्यूबर्स को रोक कर प्रताड़ित कर रहा है, शक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य कर रहा है और उसे चीन का हिस्सा बता रहा है उसके प्रतिनिधि मंडल के साथ भाजपा की दोस्ती दिखाने का क्या मतलब है? सरकारी स्तर पर दोनों देशों के बीच संबंध सुधर गए हैं। मोदी और शाह ने व्यापार की खातिर गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों का घाव भुला दिए है। प्रधानमंत्री मोदी की बहुपक्षीय मंचों पर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है तो भारत के रक्षा और विदेश मंत्री दोनों ने चीन का दौरा किया है। लेकिन पार्टी टू पार्टी यानी भाजपा और सीपीसी के नेताओं की मुलाकात या संघ और सीपीसी की मुलाकात का क्या मतलब है?

कहा जा रहा है कि एक दूसरे की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश इस मुलाकात का मकसद थी। जाहिर है कि चीन को भारत से लोकतांत्रिक प्रणाली सीखने में कोई दिलचस्प नहीं होगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी यह सीखने की कोशिश कर रही थी कि भारत में भी कैसे चीन की तरह एकदलीय व्यवस्था लागू हो सकती है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इसके अलावा भाजपा या किसी भी पार्टी को और क्या सीखा सकती है? वहां एकदलीय व्यवस्था है। कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार है और सरकारी ही पार्टी है। दूसरी बात यह है कि कोई भी नेता पार्टी और सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है। सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग हैं और उनकी हर बात का समर्थन करना सिर्फ पार्टी के नेताओं का ही नहीं, बल्कि चीन की जनता का भी पुनीत कर्तव्य है। भारत में भी पार्टी और सरकार को तो एक कर दिया गया है और यहां भी मोदी और शाह के खिलाफ बोलने को देशद्रोह माना जाने लगा है लेकिन एक बाधा विपक्ष की है। विपक्ष अब भी मजबूत है और उसके नेता भाजपा को जवाबदेह बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी हो सकता है कि सीपीसी से भाजापा ने इस मामले में कुछ टिप्स लिए हों।

इस मुलाकात के कारणों पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिलने की मजबूरी भी हो सकती है। असल में भारत लगभग पूरी तरह से चीन पर आश्रित हो गया है। रोजमर्रा की जरुरत की चीजों से लेकर कृषि सेक्टर के उपकरणों, सेमीकंडक्टर सहित ऑटोमोबाइल सेक्टर के दूसरे कंपोनेंट, आईटी सेक्टर के उपकरण, दवाओं के लिए जरूरी कंपोनेंट आदि सब चीन से आता है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 116 अरब डॉलर यानी 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। फिर भी चीन के साथ कारोबार करने की मजबूरी है। यह मजबूरी कैसी है इसे इस एक तथ्य से समझें कि भारत ने चीन के मांझे पर रोक लगाई है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राज्य गुजरात में मकर संक्रांति पर पतंगोत्सव के दौरान चीनी मांझे से गला कटने की वजह से नौ लोगों की मौत हो गई। सोचें, जिस पर पाबंदी है वह माल भी चीन से आ रहा है और खुलेआम भारत में बिक रहा है।

जी राम जी अधिनियम और लचीली एवं सतत् आजीविकाओं की दिशा में भारत की यात्रा

डॉ. विभा धवन

पिछले लगभग दो दशकों से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना का केंद्रीय स्तंभ रहे हैं। वर्ष 2005 में अधिनियमित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) ने ग्रामीण परिवारों को आय सुरक्षा प्रदान की है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार किया है तथा आवश्यक सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन में योगदान दिया है। जैसे-जैसे ग्रामीण भारत तीव्र आर्थिक, प्रौद्योगिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों से गुजर रहा है, उभरती चुनौतियों और अवसरों का प्रभावी ढंग से उत्तर देने के लिए इस ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की तात्कालिक आवश्यकता है।विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 इस क्रमिक विकास को प्रतिबिंबित करता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी ढांचे में सुधार के माध्यम से यह अधिनियम इस तथ्य को मान्यता देता है कि सतत् ग्रामीण समृद्धि केवल रोजगार सृजन पर ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलेपन तथा आजीविकाओं के संरक्षण पर भी आधारित होनी चाहिए। यह समेकित दृष्टिकोण ऐसे समय में अत्यंत प्रासंगिक है, जब ग्रामीण समुदाय जलवायु परिवर्तनशीलता, चरम मौसमीय घटनाओं और संसाधन दबाव के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता का सामना कर रहे हैं।जी राम जी अधिनियम क्यों विशिष्ट हैजी राम जी अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मजदूरी आधारित रोजगार को चार प्राथमिक क्षेत्रों के साथ संरेखित करने पर विशेष बल दिया गया हैख्र जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित अवसंरचना तथा चरम मौसमीय घटनाओं के शमन से जुड़े कार्य। यह ग्रामीण रोजगार नीति के पर्यावरणीय और लचीलापन संबंधी आयामों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।जल से संबंधित कार्य, मृदा एवं भूमि संरक्षण, जल निकासी प्रणालियाँ तथा जलवायु-अनुकूल अवसंरचना कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ बाढ़, सूखा और भूमि क्षरण के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ऐसी परिसंपत्तियां प्रभावी ढंग से नियोजित तथा कार्यान्वित की जाती हैं, तो वे कई लाभ उत्पन्न करती हैंख्रअल्पकालिक रोजगार सृजन, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन तथा दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा। इन क्षेत्रों पर अधिनियम का विशेष बल इस तथ्य को रेखांकित करता है कि रोजगार कार्यक्रम एक साथ सामाजिक संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर सकते हैं।

स्थानीय स्तर पर लचीलापनअधिनियम की नियोजन पारिस्थितिकीख्रजिसका केंद्र विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ हैं तथा जिसमें परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के अंतर्गत एकीकृत किया गया हैख्रग्रामीण विकास के लिए एक सुसंगत और भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करती है। विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से पंचायतों को स्थानीय प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर मिलता है, जबकि राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण व्यापक अवसंरचना एवं विकास उद्देश्यों के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है।कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से यह ढांचा रोजगार गारंटी के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, स्थायित्व और प्रासंगिकता में सुधार का अवसर प्रदान करता है। पर्याप्त तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से पंचायती राज संस्थान यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि सार्वजनिक कार्य, संसाधन संरक्षण तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सार्थक योगदान दें। अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित पारदर्शिता तंत्र, डिजिटल निगरानी उपकरण और सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही को और सुदृढ़ करते हैं तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं।सामाजिक संरक्षण और लचीलेपन पर ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी)सतत् विकास के प्रति वचनबद्ध एक शोध संस्थान के रूप में, टेरी ने यह समझने के लिए व्यापक रूप से कार्य किया है कि ग्रामीण समुदायों में लचीलापन विकसित करने के लिए सामाजिक संरक्षण तंत्रों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है। हमारे शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि जब रोजगार कार्यक्रमों को पर्यावरणीय योजना और जोखिम-सूचित रूपरेखा के साथ जोड़ा जाता है, तो वे घरेलू तथा सामुदायिकख्रदोनों स्तरों पर अनुकूलन क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं।टेरी ने जलवायु लचीलापन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन तथा आजीविका की निरन्तरता को सम्मिलित करने हेतु नीतिगत ढांचों के पुनरोद्धार और सुदृढ़ीकरण से संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं में विश्लेषणात्मक योगदान प्रदान किया है। इसमें कार्यक्रम अभिकल्पना में लचीलापन संबंधी पहलुओं के एकीकरण को समर्थन देना तथा रोजगार सृजन के साथ-साथ दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को प्रतिबिंबित करने वाले संकेतकों की पहचान करना शामिल है।इसके अतिरिक्त, टेरी ने ऐसे वित्तीय मॉडल और नियोजन दृष्टिकोणों का अध्ययन किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को अधिकतम करने में मदद कर सकते हैं ख्र सामुदायिक परिसंपत्तियों को सुदृढ़ करना, दीर्घकालिक संवेदनशीलता को कम करना, और संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ाना। इस प्रकार के शोध-आधारित योगदान का उद्देश्य सरकारी पहलों का पूरक होना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करना होता है।आजीविकाओं का संरक्षणजी राम जी अधिनियम का दृष्टिकोण ग्रामीण आजीविकाओं को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को प्रमुखता देता है। जल सुरक्षा, कनेक्टिविटी, भंडारण और जलवायु-सहनशील अवसंरचना में निवेश प्रत्यक्ष रूप से कृषि, सहायक गतिविधियों और गैर-कृषि आजीविकाओं का समर्थन करता है। साथ ही, अधिनियम में शामिल प्रावधान, जैसे कि प्रमुख कृषि सीजन के दौरान सार्वजनिक कार्यों में राज्य-निर्धारित विराम, यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि रोजगार सृजन कृषि गतिविधियों के पूरक के रूप में बना रहे।एक कानूनी रोजगार गारंटी की निरंतरता, साथ ही जहाँ कार्य प्रदान नहीं किया जाता वहां बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधान, अधिनियम के सामाजिक संरक्षण उद्देश्यों को और मजबूत करते हैं। पूर्वानुमेय नियोजन और वित्तपोषण के साथ, प्रशासनिक क्षमता के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से, कार्यक्रम की प्रभावशीलता और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है।शविकसित भारत 2047 की ओरजैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम समावेशी विकास प्रदान करने में एक बड़ी रणनीतिक भूमिका निभाएंगे। उनकी सफलता का मूल्यांकन केवल सृजित कार्यदिवसों की संख्या से नहीं, बल्कि लचीली आजीविकाओं, स्थायी अवसंरचना और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में उनके योगदान से किया जाएगा।इस संदर्भ में, विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचा प्रस्तुत करता है। पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को सम्मिलित करके, जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाकर और विकेन्द्रीकृत नियोजन को मजबूत करके यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को सतत् विकास की आधारशिला के रूप में स्थापित करता है। सरकार, शोध संस्थानों, राज्यों और स्थानीय समुदायों के बीच निरंतर सहयोग के माध्यम से यह सुधार यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि ग्रामीण रोजगार वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य हेतु लचीलेपन में भी सार्थक योगदान देख्रआज आजीविकाओं का समर्थन करते हुए कल की समृद्धि के लिए आवश्यक संसाधनों की रक्षा करना।

हिन्दी दैनिक जोखिम

शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

- रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अभ्यर्थियों को करना होगा पंजीकरण

- आउटसोर्स के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में होंगे तैनात

देहरादून संवाददाता.। विद्यालयी शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों एवं विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े 2364 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पदों पर भर्ती शुरू कर दी गई है। इसके लिये इच्छुक अभ्यर्थियों को कौशल विकास विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग के विभिन्न कार्यालयों व विद्यालयों में सृजित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के 2364 रिक्त पदों (मृत संवर्ग) पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके तहत कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की आधिकारिक बेवसाइट रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गये हैं। जिसकी अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती आउटससोर्स के माध्यम से की जायेगी, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने बताया कि रोजगार प्रयाग पोर्टल पर चतुर्थ श्रेणी की जनदवार रिक्तयां प्रकाशित कर दी है। जिसमें उत्तरकाशी जनपद में 135 पदों पर आवेदन मांगे गये हैं। इसी प्रकार रूद्रप्रयाग में 106, टिहरी 268, ऊधमसिंह नगर 182, पिथौरागढ़ 197, पौड़ी 340, बागेश्वर 89, अल्मोड़ा 254, चमोली 179, चम्पावत 120, देहरादून 195, हरिद्वार 91 तथा नैनीताल में 208 पदों पर भर्ती की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों को महानिदेशालय कार्यालय, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण सहित एससीईआरटी, बोर्ड कार्यालय रामनगर, मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय माध्यमिक/प्राथमिक (गढ़वाल व कुमाऊं), समस्त डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी मध्यमिक व बेसिक कार्यालय सहित इंटर कॉलेज व हाईस्कूलों में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती दी जायेगी। आउटसोर्स से तैनात कार्मिकों को प्रत्येक माह 15,000 रूपये मानदेय दिया जायेगा।

संक्षिप्त समाचार...

होटल में एनआरआई महिला की संदिग्ध मौत, मचा हड़कंप

हरिद्वार संवाददाता. सप्तऋषि इलाके के एक होटल में ठहरी एनआरआई महिला की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान 66 वर्षीय अन्ना चौहान निवासी इंग्लैंड के रूप में हुई। वह 17 सदस्यीय दल के साथ हरिद्वार आई थी। पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह अचानक अन्ना चौहान की तबीयत बिगड़ गई। होटल स्टाफ ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके जरिए महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने होटल स्टाफ और महिला के साथ आए दल के सदस्यों से भी पूछताछ की। बाद में पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। शुरुआती जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। हालांकि, असल कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो सकेगी। बेटी लंदन में डॉक्टर, परिजनों को दी गई सूचना शहर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि मृतका अन्ना चौहान की बेटी अलीशा लंदन में डॉक्टर हैं। उनको इस घटनाक्रम की सूचना दे दी गई है। बताया गया कि अन्ना चौहान दो दिन पहले ही हरिद्वार पहुंची थीं।

कोटद्वार जा रहे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका

हरिद्वार संवाददाता.कोटद्वार जा रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने चंडीघाट चौकी क्षेत्र में रोक लिया। पुलिस और भीम आर्मी के बीच काफी देर तक बहस होती रही। पुलिस ने उनको समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बनने पर सभी लोगों को रोशनाबाद ले जाकर छोड़ दिया गया। दरअसल, कोटद्वार की एक दुकान पर 'बाबा' लिखे जाने के मामले को लेकर बीते कई दिनों से विवाद जारी है। इसी मामले में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह कार्यकर्ताओं के साथ कोटद्वार में दीपक के समर्थन में जाने वाले थे। लेकिन, पुलिस ने चंडीघाट चौकी क्षेत्र में रोक लिया, जहां दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बात होती रही। सीओ सिटी शिशुपाल, नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह और इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस की ओर से वीडियो कॉल के जरिये दीपक से बात कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता पुलिस चौकी से बाहर निकलकर अपने वाहनों से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। यह देख पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को पकड़कर रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन ले आई, जहां से कुछ देर बाद उनको छोड़ दिया गया।

अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार संवाददाता. जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला के निर्देशन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आबकारी निरीक्षक दर्शन सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम ने बहादराबाद तिराहे के पास चेकिंग के दौरान दोपहिया सवार को रोककर तलाशी ली। उसके पास से अंग्रेजी शराब के 87 पव्वे मिले। आरोपी की पहचान गौरव चौरसिया उर्फ चीनू के रूप में हुई है। आबकारी टीम ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया। बिंजोला ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

लघु व्यापारियों की नई इकाई के कमल अध्यक्ष और महामंत्री बने दयाराम

हरिद्वार संवाददाता. मनसा देवी सीढ़ी मार्ग के लघु व्यापारियों ने स्वतंत्रता सेनानी पार्क में हुई बैठक में लघु व्यापार संगठन की नई इकाई का गठन किया। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने अध्यक्षता, जबकि जिलाध्यक्ष राजकुमार ने संचालन किया। इस दौरान सर्वसम्मति से कमल प्रताप चौहान को मनसा देवी सीढ़ी मार्ग के लघु व्यापारियों की नई इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सपना गोस्वामी को उपाध्यक्ष, दयाराम को महामंत्री, शशिकांत को कोषाध्यक्ष और विजय सिंह को मीडिया प्रभारी बनाया गया। जुगल किशोर, आर्यन गोस्वामी, दिग्विजय सिंह, पिंकी, सुरेश गिरी, उमाशंकर, सचिन, पवन त्रिवेदी, जोगेंद्र जग्गी गोस्वामी, मनीष शर्मा और राजकुमार को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने फूल-मालाएं पहनाकर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया।

मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं मिली, औषधि की बिक्री पर रोक

देहरादून संवाददाता. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। प्रतिष्ठान के औषधियों के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी के निर्देशों के तहत सेफ ड्रग, सेफ लाइफ अभियान के अंतर्गत कोडीन युक्त कफ सिरप एवं अन्य औषधीय की अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को औषधि निरीक्षक विनोद जगूड़ी द्वारा विकासनगर, डाकपत्थर एवं सेलाकुई क्षेत्र स्थित विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

आयोग ने छह परीक्षाओं का अपडेट परीक्षा कैलेंडर जारी किया

हरिद्वार संवाददाता. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को छह प्रमुख परीक्षाओं का अपडेटेड कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां घोषित की गई हैं। परीक्षा नियंत्रक जयवर्धन शर्मा के अनुसार, उत्तराखंड सचिवालय एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव परीक्षाख्र2024 की मुख्य परीक्षा 14 मार्च को होगी। महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका परीक्षाख्र2026 की स्क्रीनिंग 22 मार्च को प्रस्तावित है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षाख्र2023 की मुख्य परीक्षा 21 से 24 अप्रैल के बीच होगी। कार्मिक विभाग की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षाख्र2025 की मुख्य परीक्षा 27 से 30 अप्रैल 2026 तक कराई जाएगी। सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 की साक्षात्कार परीक्षा 16 मार्च से प्रस्तावित है। प्रवक्ता की मुख्य परीक्षाएं नौ मई से माध्यमिक शिक्षा विभाग की राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षाख्र2025 के अंतर्गत 9 मई को भौतिक विज्ञान, 10 मई को नागरिक शास्त्र, 30 मई को हिंदी और 31 मई को इतिहास विषय की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा-2024 के शेष विषयों की तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। सहायक निदेशक की भर्ती परीक्षा स्थगित डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत सहायक निदेशक परीक्षाख्र2025 पूर्व में 12 अप्रैल को प्रस्तावित थी, उसे अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड सचिवालय/उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) परीक्षाख्र2024 की मुख्य परीक्षा 3 और 4 सितंबर 2025 को हो चुकी है। मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद कंप्यूटर परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी।

सोहलपुर रोड पर अतिक्रमण से जायरीन परेशान

रुड़की संवाददाता. कलियर के सोहलपुर रोड पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के चलते आए दिन भारी जाम लग रहा है। सड़क के दोनों ओर लगी रेहड़ी-ठेलियों, दुकानों और गेस्ट हाउसों के सामने खड़ी गाड़ियों के कारण मार्ग संकरा हो गया है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इस मार्ग से साबिर पाक की जियारत के लिए बड़ी संख्या में जायरीन आते हैं। जाम लगने के कारण जायरीनों के साथ-साथ स्थानीय लोगों और राहगीरों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार बड़े वाहनों के फंस जाने से सड़क पूरी तरह बंद हो जाती है और लंबा जाम लग जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोहलपुर रोड पर लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। सड़क किनारे अस्थायी दुकानें और रेहड़ी-ठेलियां लगने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। वहीं गेस्ट हाउसों के सामने वाहन चालक मनमाने ढंग से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है।

मोहल्ले की गलियों में लगे हैं कूड़े के ढेर

रुड़की संवाददाता. मंगलवार को तहसील दिवस में एसडीएम सौरभ सिंह असवाल ने लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। उन्होंने 35 शिकायतों में से 13 का मौके पर समाधान कराया। अधिवक्ताओं ने कस्बे के कई मोहल्लों में नियमित साफ सफाई नहीं होने की शिकायत की। उन्होंने मोहल्ले की गलियों में लगे कूड़े के ढेर की तस्वीरें भी दिखाई। इससे नाराज एसडीएम ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को सफाई करने के लिए सख्त हिदायत दी। इससे पहले तहसील दिवस के दौरान भी कस्बे में गंदगी को लेकर सीडीओ ने अधिशासी अधिकारी के वेतन पर रोक लगाई थी।

हाईवे पर विज्ञापन चिपकाएं, नौ के खिलाफ एफआईआर दर्ज

हरिद्वार संवाददाता. नेशनल हाईवे की दीवार-पिलर और फ्लाईओवर पर बिना अनुमति पोस्टर-बैनर और अवैध तरीके से लिखकर विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मामले में एनएचएआई ने कनखल थाने में नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर यह कदम उठाया गया। पीआईयू हरिद्वार के महाप्रबंधक एवं सह परियोजना निदेशक विशाल कुमार गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-334 पर निर्माण पूरा होने के बाद अवैध तरीके से विज्ञापन और प्रचार किया जा रहा है, जो दंडनीय अपराध है। बार-बार चेताने के बावजूद डॉ. करन, सांची क्लीनिक, सदाशिव इंफ्रा, डॉ. भारत, भगंदर क्लीनिक, डॉ. सिंघला, गुरु कृपा, एएफआई पशु आहार और जेके मैक्स ने अपना प्रचार बंद नहीं किया। इस पर नौ फर्म स्वामियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एनएचएआई के अनुसार, बाकी लोगों को भी चिह्नित किया जा रहा है। एफआईआर के बाद हटने लगे अवैध प्रचार नेशनल हाईवे पर अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती के बाद विज्ञापनदाताओं में हलचल मच गई। एनएचएआई के अनुसार, एफआईआर के तुरंत बाद डॉ. करन ने अपने विज्ञापन हटाने शुरू कर दिए हैं। बाकी लोगों को भी अपने-अपने विज्ञापन हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

धनोल्टी में सफाई व्यवस्था कर पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाएं

नई टिहरी संवाददाता. पर्यटन नगरी धनोल्टी में तहसील दिवस आयोजित किया गया। डीएम नितिका खंडेलवाल ने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को तहसील दिवस में दर्ज शिकायतों का जल्द निस्तारण कर अवगत कराने के निर्देश दिए। धनोल्टी में आयोजित तहसील दिवस में पर्यटन नगरी धनोल्टी में सफाई व्यवस्था करने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाने की मांग उठाई गई। ग्राम गोठ के प्रधान लाखीराम चमोली ने धनोल्टी से लग्गा गोठ तक सड़क बनाने, जीआईसी धनोल्टी चुलीसैण में कला वर्ग के लिए पदों का सृजन करने, क्षेत्र में आधार कैंप लगाने, लग्गा गोठ में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग की। स्थानीय पशुपालकों ने पशुओं का बीमा और टीकाकरण कराने की मांग उठाई। लामकंडे के प्रधान दिनेश रावत ने आपदा से क्षतिग्रस्त संपत्तियों का मुआवजा देने, सौंग नदी पर बने चेकडैम से कृषि भूमि को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए सुरक्षा दीवार लगाने और चुनारी गाड से गांव की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार लगाने की मांग उठाई गई। गांव की मंजू देवी ने प्रधानमंत्री आवास देने और क्षेत्र की भोजन माताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग की। धनोल्टी टैक्सी-मैक्सी एसोसिएशन ने टैक्सी स्टेंड के लिए जमीन देने की मांग की। जिला पंचायत सदस्य दीक्षा नेगी ने क्षेत्र में आधार केंद्र खोलने, खनेरी-धनोल्टी मोटर मार्ग को जोड़ने की मांग की। तहसील दिवस में धनोल्टी-कद्दूखाल क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण करने, विद्युत लाइनों को प्रभावित कर रहे पेड़ों की लॉपिंग करने, नेटवर्क समस्या से निजात दिलाने, निराश्रित गोवंश के लिए पार्किंग के नीचे गोशाला बनाने की मांग की गई। डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम अंकित राज और तहसीलदार बीरम सिंह आदि मौजूद थे।

तहसील दिवस : प्रशासन से उठता जनता का भरोसा

चमोली संवाददाता. क्षेत्र में बदहाल सड़कें, लगातार बढ़ता मानव-वन्यजीव संघर्ष, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी गंभीर समस्याओं के बावजूद तहसील दिवस में जनता का न पहुंचना प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मंगलवार को पोखरी तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस में सभी विभागीय अधिकारी तय समय पर मौजूद रहे लेकिन एक भी फरियादी अपनी शिकायत लेकर नहीं पहुंचा। यह लगातार दूसरा महीना है जब तहसील दिवस शिकायत-विहीन रहा। हर माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित होने वाला तहसील दिवस जनता को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखने का अवसर देता है। जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान न होने के कारण अब लोग इन मंचों से दूरी बनाने लगे हैं। तहसीलदार जितेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित इस तहसील दिवस में विभिन्न विभागों के अधिकारी लंबे समय तक फरियादियों का इंतजार करते रहे लेकिन कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। वहीं, सिनाऊ पल्ला के ग्राम प्रधान तेजपाल निर्मोही, किमोठा के प्रधान हरिकृष्ण किमोठी, कांडई चंद्रशिला के प्रधान भगत भंडारी और गजेंद्र नेगी का कहना है कि जब पहले दी गई शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं होती और समाधान सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है तो लोग शिकायत दर्ज कराने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। यदि शिकायतों की नियमित मॉनीटरिंग हो और समाधान धरातल पर दिखाई दे, तभी जनता दोबारा तहसील दिवस में विश्वास जताएगी।तहसील दिवस में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार, बीडीओ शिव सिंह भंडारी, सीएचसी अधीक्षक डॉ. प्रियम गुप्ता, पीएमजीएसवाई के अधि शासी अभियंता मनमोहन बिजलवाण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन फरियादियों की गैरमौजूदगी ने प्रशासन और जनता के बीच बढ़ती दूरी को साफ तौर पर उजागर कर दिया।

अतिक्रमण और अवैध पार्किंग ने छीनी चमियाला की रफ्तार

नई टिहरी संवाददाता. चमियाला बाजार क्षेत्र के लोगों को जाम की समस्या से राहत नहीं मिल पा रही है। आए दिन लगने वाला जाम स्थानीय लोगों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी करने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दूर दराज गांवों से जरूरत का सामान लेने आए लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। बाजार क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और पार्किंग सुविधा के अभाव ने स्थिति गंभीर बनती जा रही है।चमियाला भिलंगना क्षेत्र का मुख्य बाजार होने के कारण दूर-दराज के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं लेकिन पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने से लोग मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। इससे सड़क संकरी हो जाती है। थोड़ी सी भी भीड़ बढ़ने पर यातायात ठप हो जाता है। लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है।

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर दिया जोर

नई टिहरी नगर पंचायत गजा की ओर से गठित महिला समूहों व अन्य महिलाओं की गजा नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर सिंह चौहान के नेतृत्व में बैठक हुई जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष चौहान ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आजीविका बढ़ना है। कृषि वैज्ञानिक डॉ॰ सचिन कुमार, डॉ॰ कीर्ति, डॉ॰ एकता बेलवाल ने कृषि एवं बागवानी, एसबीआई के शाखा प्रबंधक प्रशांत कुमार, आरसेटी के संजीव नेगी, सुनील कुमार समूह को बैंक से दिए जाने वाले ऋण तथा अन्य लोगों ने मातृ वंदना, जननी सुरक्षा, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बैठक में मौजूद महिलाओं को बताया। जिला पंचायत सदस्य ताजवीर सिंह खाती ने महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आजीविका बढ़ाने की अपील की। इस मौके पर अरविंद जोशी, दिनेश सिंह आदि मौजूद थे।

पटूड़ी गांव ने ठाना नशे को नहीं मिलेगी पंचायत की धरती

नई टिहरी संवाददाता. जाखणीधार ब्लॉक के पटूड़ी गांव में ग्राम पंचायत की खुली बैठक के दौरान ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से गांव को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। बैठक में मांगलिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया गया। गांव की दुकानों के आसपास और सार्वजनिक स्थलों पर ताश खेलने पर भी रोक लगाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर ग्राम पंचायत की ओर से 51 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा। मंगलवार को ग्राम प्रधान विजय लाल शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने नशे को समाज के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि शादी, मेहंदी, मुंडन, जन्मदिन और शादी की सालगिरह आयोजनों में खुलेआम शराब परोसे जाने से खासकर युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है जो भविष्य के लिए चिंताजनक है। ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो सामाजिक ताना-बाना कमजोर पड़ सकता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा की सीमा के भीतर शराब का क्रय-विक्रय पूरी तरह बंद रहेगा। पंचायत स्तर पर सामाजिक निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी, ताकि तय नियमों का प्रभावी ढंग से पालन हो सके। पहाड़ की पुकार संस्था की संस्थापक अवंतिका भंडारी ने ग्रामीणों की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज ही स्वस्थ और सशक्त भविष्य की नींव रखता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि संस्था इस मुहिम में पंचायत और ग्रामीणों को हर संभव सहयोग देगी। बैठक में आशा रावत, मीनू टम्टा, अंजलि कठियाल, रौनकी देवी, दयाल सिंह नेगी, बलराज, निलिख, रणवीर, पवन, पृथ पाल, महावीर लाल, प्रेम सिंह, कलम नेगी, जितार सिंह, रोशन लाल, अषाड़ी देवी, सोबती देवी, प्रभा देवी, सरिता, सरस्वती, कुशला आदि मौजूद रहे।

पुनर्वास का कार्य टीएचडीसी को सौंपने पर जताया आक्रोश

नई टिहरी संवाददाता.। टिहरी बांध विस्थापितों और प्रभावितों ने पुनर्वास का कार्य टीएचडीसी से हटाने की मांग की है। उन्होंने पुनर्वास का कार्य पूर्व की भांति सिंचाई विभाग की देने की मांग उठाई है। जल्द ही मामले में सकारात्मक कार्रवाई न होने पर डीएम/पुनर्वास निदेशक कार्यालय में ध रना शुरू करने की चेतावनी दी है। टिहरी बांध प्रभावित व विस्थापित गांव के जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को डीएम/पुनर्वास निदेशक नितिका खंडेलवाल से मिला। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर पुनर्वास का कार्य टीएचडीसी से हटाने की मांग की। कहा कि जब से पुनर्वास का कार्य टीएचडीसी के पास गया है, तब से कोई भी मामले निस्तारित नहीं हो रहे हैं। टीएचडीसी के अधिकारी कार्यों को लटका रहे हैं। जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो प्रभावित एवं विस्थापित परिवार डीएम कार्यालय परिसर में धरना शुरू करेंगे। जब तक सभी प्रभावितों का पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक यह कार्य टीएचडीसी को देने का कोई औचित्य नहीं है। हनुमंत राव कमेटी, केंद्र सरकार की गाइडलाइन और पुनर्वास नीति में स्पष्ट है कि पुनर्वास का कार्य राज्य सरकार करेगी। टीएचडीसी केवल धनराशि की व्यवस्था करेगी। टीएचडीसी एक कंपनी है जिसका सभी विस्थापित परिवार विरोध कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व ब्लॉक प्रमुख खेम सिंह चौहान, पूर्व प्रधान राजेंद्र कुमाई, विजयपाल चौहान, युद्धवीर सिंह, सोबन सिंह, रौलाकोट के ग्राम प्रधान अरविंद नौटियाल शामिल रहे।

पीएमश्री इंटर कॉलेजों के छात्रों का दल शैक्षिक भ्रमण पर हैदराबाद रवाना

नई टिहरी संवाददाता. पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं का एक दल शैक्षिक भ्रमण के लिए हैदराबाद के टूर पर रवाना किया गया है। सीडीओ वरुणा अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत ने छात्रों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छह शिक्षक-शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में 70 छात्र-छात्राओं को भ्रमण पर भेजा गया है। छात्र-छात्राओं को प्रसिद्ध संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराने के लिए मंगलवार को टिहरी जिले के विभिन्न स्कूलों में कक्षा नौ और 11वीं में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को उनके शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए सात दिवसीय शैक्षिक भ्रमण पर हैदराबाद भेजा गया है। इस दौरान मौके पर पहुंची डीएम नितिका खंडेलवाल ने भी छात्रों से बातचीत की। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य सुनील जुयाल, सभासद विजय कठैत, डीईओ माध्यमिक वीपी सिंह और सुरेंद्र सिंह नकोटी आदि मौजूद रहे।

पीटीए की बैठक में परीक्षाओं की तैयारियों पर हुई चर्चा

चमोली संवाददाता. जनता इंटर कालेज बूंगा-नैणी में आयोजित शिक्षक-अभिभावकों की बैठक में वार्षिक गृह परीक्षा, परिषदीय परीक्षा की तैयारियों पर परिचर्चा की गई। प्रधानाचार्य संतोष नैनवाल ने सभी अभिभावकों से बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे पाल्यों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय देने का सुझाव दिया। बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के उपरांत गृह परीक्षा का कार्यक्रम तय है। इसलिए गृह परीक्षा के परीक्षार्थियों को भी परीक्षा की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय की दोनों परीक्षाओं का परीक्षाफल शत प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अभिभावकों से विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सीएम देवराड़ी, रघुवीर सिंह, कुंवर सिंह, नारायण सिंह, कमला देवी, देवकी देवी, बिमला देवी आदि अभिभावक मौजूद रहे।

जन कल्याण लोक सेवा समिति गौचर की बैठक हुई आयोजित

चमोली संवाददाता.जन कल्याण लोक सेवा समिति की ओर से आयोजित बैठक में लोक संस्कृति की सामूहिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जन समस्याओं के निराकरण की दिशा में समिति की ओर से मजबूत पैरवी करने का निर्णय लिया गया। समिति के अध्यक्ष सुनील पंवार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। और सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि एक मार्च को मेला मंच में भव्य होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमें पालिका क्षेत्र की कीर्तन मंडलियों, महिला मंगल दलों, व्यापार संघ सहित सभी संगठनों को आमंत्रित करने के सुझाव पर सहमति जताई गई। बैठक में खुशाल सिंह नेगी, गोविंद सिंह नेगी, शिव चरण बिष्ट आदि ने विचार व्यक्त किए।

ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई के खिलाफ निकाली रैली, पुतला फूंका

चमोली संवाददाता. सेलंग-सलूड़ डुंग्रा मोटर मार्ग की मरम्मत में अनियमितता और विभागीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने ज्योतिर्मठ में पीएमजीएसवाई का पुतला फूंका। ग्रामीणों ने 15 दिन में वित्तीय अनियमितता पर कार्रवाई और निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। रम्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध सलूड़ डुंग्रा गांव की सड़क 80 के दशक में बनी थी। वर्तमान में सड़क की स्थिति बदहाल है। सेलंग से सलूड़ डुंग्रा तक करीब आठ किमी लंबी इस सड़क की मरम्मत के लिए शासन ने तीन साल पहले 8.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। इसमें पहाड़ कटान, चौड़ीकरण, डामरीकरण व अन्य सुधारीकरण कार्य किए जाने हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि तीन साल से चल रहा कार्य न तो अभी तक पूरा हुआ है और जो कार्य हुआ है न ही उसकी गुणवत्ता बेहतर है। कहीं डामर नहीं किया गया है तो कहीं पुरानी दीवार को खोलकर नई दीवार बना दी गई।

हिन्दी दैनिक जोखिम

सीएम धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमओयू एवं ग्राउंडिंग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई

- स्पिरिचुअल जोन, आयुर्वेद एम्स और भराड़ीसैंण में मंदिर अवसंरचनात्मक निर्माण को प्राथमिकता में लेने के मुख्यमंत्री के निर्देश

देहरादून संवाददाता. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत हुए एमओयू तथा उनकी ग्राउंडिंग (क्रियान्वयन) की प्रगति की समीक्षा हेतु उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए एमओयू की वर्तमान स्थिति, जमीनी प्रगति, अवरोधों तथा आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई।एमओयू ग्राउंडिंग में ऐतिहासिक प्रगति, मुख्यमंत्री ने बताया राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि: बैठक में अवगत कराया गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत कुल 3,57,693 करोड़ रुपये के 1,779 एमओयू संपादित किए गए थे, जिनमें से अब तक 1,06,953 करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंडिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के औद्योगिक एवं आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह राज्य में निवेशकों के विश्वास, बेहतर कानून-व्यवस्था, सुशासन और उद्योग अनुकूल वातावरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस सकारात्मक परिणाम को और आगे बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं

मौजूद हैं, जिनका लाभ राज्यहित में लिया जाना चाहिए।एमओयू ग्राउंडिंग में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री के स्पष्ट और सख्त निर्देश:मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि एमओयू एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर आ रहे अवरोधों का त्वरित निस्तारण किया जाए।प्रत्येक संबंधित विभाग में एक-एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो एमओयू ग्राउंडिंग की सतत मॉनिटरिंग करे। यदि किसी नीति में संशोधन, सरलीकरण अथवा शिथिलीकरण की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र पैरवी की जाए। उद्योगपतियों के साथ नियमित संवाद और संपर्क बढ़ाया जाए तथा उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटलीकरण,सरलीकृत प्रक्रियाएं और उद्योग फ्रेंडली इकोसिस्टम से संबंधित सुधारों की जानकारी दी जाए। निर्देश दिए कि परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में अनावश्यक देरी बिल्कुल न हो, कार्यों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, स्पष्ट टाइमलाइन के अनुसार कार्य पूर्ण हों और किसी भी प्रकार की पेंडेंसी न रखी जाए।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ विभागों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, जिसकी उन्होंने प्रशंसा भी की।पर्यटन, उद्योग और निवेश के नए अवसरों पर विशेष फोकस:मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को निर्देशित किया कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जिन क्षेत्रों में होटल निर्माण की व्यापक संभावनाएं हैं,ख़ जैसे पिथौरागढ़, कैंची धाम सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलोंख़वहाँ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग स्पेशल टूरिस्ट जोन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एरिया आधारित फोकस पॉलिसी तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। उद्योगों को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि राज्य के सभी जनपदों में प्रत्येक माह "उद्योग मित्र समिति" की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें उद्योगों से जुड़े मुद्दों का समाधान तथा उद्योग-अनुकूल निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

समान कार्य, समान वेतन' के रूप में सीएम धामी ने दर्ज की एक और उपलब्धि

देहरादून संवाददाता. उपनल कर्मियों को दस वर्ष की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने का शासनादेश जारी होने के साथ ही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। उपनल कर्मी अपनी विभिन्न मांगों के लिए लंबे समय से आंदोलनरत थे, इस बीच कई सरकारें बदली। आखिरकार अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उपनल कर्मियों को दस साल की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन मिलने का शासनादेश जारी हो गया है। यह उपलल कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

उत्तराखंड में पर्वतारोहण को नई उड़ान.. 83 प्रमुख हिमालयी चोटियां पर्वतारोहियों के लिए खुलीं

देहरादून संवाददाता. देवभूमि उत्तराखंड ने साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्वतारोहण को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (न्क्ट) ने वन विभाग के समन्वय से गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय क्षेत्र की 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण अभियानों के लिए पूरी तरह खोल दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड को वैश्विक पर्वतारोहण मानचित्र पर एक सशक्त और आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। खोली गई चोटियों की ऊंचाई 5,700 मीटर से 7,756 मीटर तक है, जिनमें कामेट (7,756 मीटर), नंदा देवी ईस्ट, चौखंबा समूह, त्रिशूल समूह, शिवलिंग, सतोपंथ, चंगाबांग, पंचचूली और नीलकंठ जैसी विश्व प्रसिद्ध और चुनौतीपूर्ण चोटियां शामिल हैं। ये शिखर न केवल तकनीकी कठिनाई और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि हिमालय की भव्यता के जीवंत प्रतीक भी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारी शक्ति है। 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोलना राज्य के साहसिक पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। हमारा उद्देश्य है कि देश के युवा पर्वतारोहण जैसे साहसिक क्षेत्रों में आगे आएं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित विकास सुनिश्चित हो। राज्य सरकार सुरक्षित, जिम्मेदार और सतत पर्वतारोहण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सीमावर्ती व दूर-दराज क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। भारतीय पर्वतारोहियों को बड़ी राहत: अधिसूचित 83 चोटियों पर अब भारतीय पर्वतारोहियों को कोई अभियान शुल्क (पीक फीस, कैंपिंग फीस, पर्यावरण शुल्क् आदि) नहीं देना होगा।

जन-जन के द्वारा अभियान के तहत वृहद बहुउउदेशीय शिविर का आयोजन

हल्द्वानी संवाददाता. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानीबाग में 04 फरवरी (बुधवार) को जन-जन की सरकार जन-जन के द्वारा अभियान के तहत वृहद बहुउउदेशीय शिविर का आयोजन किया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डे ने बताया कि उक्त शिविर में सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखंड शासन चन्द्रेश कुमार द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि शिविर में सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर जानकारियों से लाभान्वित किया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सचिव द्वारा शिविर के पश्चात क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सचिव श्री चन्द्रेश कुमार द्वारा 05 फरवरी प्रात: 10:30 बजे कलक्ट्रेट सभागार नैनीताल में जनपद में हो रहे विकास कार्यों योजनाओं के सम्बन्ध में जिला स्तरीय अधिकारियो तथा विभिन्न स्टेक होल्डर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा।

लालकुआँ बिंदुखत्ता में वन सुरक्षा दस्ते की बड़ी कार्रवाई

बिना नंबर ट्रैक्टरख़ट्रॉली में अवैध आर.बी.एम. परिवहन पकड़ा, चालक मौके से फरार!

लालकुआँ संवाददाता. बिंदुखत्ता क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान कालिका मंदिर के समीप वन सुरक्षा दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन सामग्री के परिवहन का खुलासा किया।गश्त कर रही टीम को एक बिना नंबर प्लेट की ट्रैक्टरख़ट्रॉली संदिग्ध अवस्था में आर.बी.एम. (खनिज सामग्री) ले जाते हुए दिखाई दी। जब वन सुरक्षा कर्मियों ने वाहन को रोकने का इशारा किया तो चालक ट्रैक्टरख़ट्रॉली को रास्ते में ही खड़ा कर आबादी क्षेत्र की ओर फरार हो गया।मौके पर जांच करने पर पाया गया कि ट्रैक्टरख़ट्रॉली में लदी आर.बी.एम. के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज (रवन्ना/अनुमति पत्र) मौजूद नहीं थे।

संक्षिप्त समाचार...

उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन के जिओ जारी होने पर जताया आभार

देहरादून संवाददाता. सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से आज उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने उनके कैंप कार्यालय में भेंट कर 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्यख़समान वेतन का लाभ दिए जाने का जिओ जारी होने पर मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर एमडी उपनल ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट, उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री गणेश जोशी ने की मसूरी विस क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा

देहरादून संवाददाता.। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में जल निगम, जल संस्थान एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित एवं संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चामासारी, सरोना सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं को तीन दिन के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर विशेष जोर दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पुश्ता निर्माण सहित अन्य कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कोटद्वार प्रकरण में दीपक के समर्थन में उतरी भीम आर्मी

हल्द्वानी संवाददाता. कोटद्वार प्रकरण में युवकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे रद करने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजे ज्ञापन में कहा कि मुस्लिम दुकानदार की मदद करने वाले दीपक कुमार और विजय रावत पर तथाकथित संगठन के दबाव में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जबकि संगठित होकर हमला करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

हिन्दी दैनिक जोखिम

लालकुआं /बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिले देवेंद्र बिष्ट, सौंपा ज्ञापन!

लालकुआं संवाददाता. बिंदुखत्ता क्षेत्र को राजस्व गांव घोषित कराने की मांग को लेकर भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश मंत्री (ओबीसी मोर्चा) देवेंद्र सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत बिंदुखत्ता (नैनीताल) को राजस्व गांव घोषित करने की अधिसूचना शीघ्र जारी करने की मांग रखी।देवेंद्र बिष्ट ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 20 सितंबर 2024 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति नैनीताल द्वारा बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है। नियमों के तहत आपत्तियों का निस्तारण एवं अपील की प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद अब तक अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है, जिससे क्षेत्रवासियों को राजस्व गांव का लाभ नहीं मिल पा रहा है।उन्होंने कहा कि बिंदुखत्ता के हजारों परिवार वर्षों से बुनियादी सुविधाओं, भूमि अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। राजस्व गांव का दर्जा मिलने से क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।मुख्यमंत्री ने ज्ञापन पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कराने का भरोसा दिलाया। देवेंद्र बिष्ट की इस पहल को क्षेत्रवासियों ने सराहनीय बताते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा।

क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर 2.35 लाख ठगे

रुद्रपुर संवाददाता. रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति से क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 2.35 लाख रुपये की ठगी कर ली। तहरीर पर थाना पंतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, शक्ति विहार कॉलोनी जगतपुरा, रुद्रपुर निवासी खुमान लाल भटपुरिया ने बताया कि 22 जनवरी की शाम उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने स्वयं को बैंक का प्रतिनिधि बताते हुए क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की बात कही। इसके बाद ठग ने व्हाट्सएप के माध्यम से एक एपीके फाइल भेजी, जिसे खोलते ही उनका मोबाइल हैक हो गया। आरोप है कि इसके बाद ठग व्हाट्सएप कॉल पर लगातार उन्हें बातों में उलझाए रहा और इसी दौरान उनके क्रेडिट कार्ड व बैंक खाते से रुपये कटते रहे। जब उनके बेटे ने उनकी पत्नी के फोन पर कॉल कर पूरे मामले की जानकारी ली, तब ठगी का शक हुआ। बेटे की सलाह पर उन्होंने तत्काल कॉल बंद कर कस्टमर केयर से संपर्क किया। जांच में सामने आया कि उनके क्रेडिट कार्ड से 2 लाख 20 हजार 259 रुपये और बैंक खाते से 15 हजार 48 रुपये निकाल लिए गए थे। थानाध्यक्ष पंतनगर नंदन सिंह रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोबाइल नंबर, एपीके फाइल और ट्रांजेक्शन डिटेल के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

कल्याणी नदी में बिना ट्रीटमेंट पानी छोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई

रुद्रपुर संवाददाता. कल्याणी नदी को प्रदूषणमुक्त बनाने के उद्देश्य से सिडकुल में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को जिला सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसमें सीडीओ दिवेश शाशनी ने निर्देश दिए कि बिना ट्रीटमेंट किया गया पानी यदि कल्याणी नदी में छोड़ा गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ ने कहा कि सभी

औद्योगिक इकाइयां अपने-अपने ट्रीटमेंट प्लांटों में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करें। एक माह बाद कंपनियों से निकलने वाले पानी की सैंपलिंग कर जांच कराई जाएगी। जांच में यदि किसी भी कंपनी का दूषित पानी कल्याणी नदी में गिरता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीडीओ ने आरएम सिडकुल एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को औद्योगिक इकाइयों में स्थापित ट्रीटमेंट प्लांटों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन कंपनियों में खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उनकी सूची तैयार कर नियमित जांच करने को कहा। इसके अलावा कल्याणी नदी के जल की गुणवत्ता जांच के लिए सिडकुल में प्रवेश से पूर्व, सिडकुल क्षेत्र समाप्ति के बाद अटरियां मंदिर के पास और शहर समाप्ति के बाद उत्तर प्रदेश सीमा पर सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए गए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस क्षेत्र में नदी का पानी कितना प्रदूषित हो रहा है। बैठक में एडीएम पंकज उपाध्याय, एसडीएम एवं आरएम सिडकुल मनीष बिष्ट, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपी सिंह, सहायक अभियंता सुनील कुमार, दिलदार अली सहित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के एचआर हेड मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय हल्द्वानी दौरे पर

हल्द्वानी संवाददाता. /मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार से दो दिवसीय हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शहर में विभिन्न

कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं तथा सुरक्षा और यातायात को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।प्रशासनिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बुधवार को दोपहर 1 बजे एफटीआई मैदान पहुंचेंगे, जहां से वे रामपुर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में शामिल होंगे। इसके पश्चात अपरान्ह 3 बजे एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित शिव कथा कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जमरानी बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। इसके तहत बुधवार को दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान प्रभावी रहेगा। भारी माल वाहनों के लिए रूद्रपुर/रामपुर रोड से टीपी नगर क्षेत्र की ओर आने वाले वाहन गन्ना सेंटर तिराहा से डायवर्ट होकर बरेली रोड के माध्यम से जाएंगे, जबकि टीपी नगर से रूद्रपुर/रामपुर रोड की ओर जाने वाले भारी वाहन सतवाल पेट्रोल पंप से मुक्त विश्वविद्यालय होते हुए तीनपानी से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।रूद्रपुर/रामपुर रोड से रोडवेज स्टेशन हल्द्वानी आने वाली रोडवेज बसों को गन्ना सेंटर तिराहा से बरेली रोड व तीनपानी होते हुए मंडी मार्ग से स्टेशन भेजा जाएगा। वहीं सिडकुल और प्राइवेट बसों के लिए काठगोदाम, मुखानी और लालढांठ क्षेत्रों की ओर अलग-अलग डायवर्जन रूट निर्धारित किए गए हैं। छोटे वाहनों को भी रामपुर रोड और पर्वतीय क्षेत्रों से आने-जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा।मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के दौरान वीआईपी रूट पर जीरो जोन व्यवस्था लागू रहेगी। वीआईपी मार्ग पर पड़ने वाले सभी कटों से किसी भी प्रकार के वाहन को मुख्य मार्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित डायवर्जन रूट का पालन करें और सुरक्षा एवं कार्यक्रम व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

अल्मोड़ा बैडमिंटन कप 2026 का शुभारंभ, खिलाड़ियों में उत्साह

अल्मोड़ा संवाददाता. जिला बैडमिंटन संघ अल्मोड़ा की ओर से आयोजित अल्मोड़ा बैडमिंटन कप 2026 का विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया गया। 02 दिवसीय टूर्नामेंट में विभिन्न आयु वर्गों के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों ने

उत्साह के साथ भाग लिया। ओपन सीनियर वर्ग के पहले मुकाबले में डी. के. जोशी और नवनीत कुमार की जोड़ी ने अरुण बंगयाल और प्रतीक मेहरा की जोड़ी को 21-14 और 21-7 से पराजित कर विजयी शुरुआत की। एक अन्य मुकाबले में सुरेश कर्नाटक और हरीश अधिकारी की जोड़ी ने रमेश बिष्ट और रमेश बोरा की जोड़ी को सीधे सेटों में हराकर अगले चरण में प्रवेश किया। उद्घाटन अवसर पर कुलपति एस. एस. जे. विश्वविद्यालय डॉ. सतपाल सिंह बिष्ट, नैनीताल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार लाल, पूर्व कुलपति डॉ. जगत सिंह बिष्ट, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. डी. एस. बिष्ट, जिला क्रीड़ा अधिकारी महेशी आर्य, उत्तरांचल बैडमिंटन संघ के महासचिव बी. एस. मनकोटि सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष सुरेश कर्नाटक,मीडिया प्रभारी डी. के. जोशी, उप क्रीड़ा अधिकारी अरुण बंगयाल, टूर्नामेंट रेफरी जीवन बोरा सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक और खेल प्रेमी मौजूद रहे। 04 फरवरी को टूर्नामेंट का समापन होगा।

पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, फायरिंग का आरोप

रुद्रपुर संवाददाता. काशीपुर हाईवे पर पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार युवकों पर जानलेवा हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस दौरान हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग भी की। परिजनों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा पुलिस को घटना की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार, रुद्र विलास चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डिबडिबा निवासी विक्की सोमवार देर रात अपने साथी श्रवण सिंह के साथ बाइक से ग्रीन पार्क गया था। देर रात घर लौटते समय रास्ते में घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि डिबडिबा क्षेत्र में दो कारों में सवार युवकों ने जानबूझकर बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद कार सवार युवकों ने विक्की पर लाठी-डंडों और हथियारों से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग भी की। फायरिंग और शोर-शराबे की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र होने लगे। भीड़ जुटती देख हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना में विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि श्रवण सिंह को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल विक्की को रामपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

तू या मैं में मेरा किरदार साइड रोल नहीं, कहानी की मजबूत कड़ी है: पारुल गुलाटी

बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में लगातार अपनी अलग पहचान बना रहीं अभिनेत्री पारुल गुलाटी इन दिनों अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं। अभिनय के साथ-साथ एक सफल उद्यमी के तौर पर भी अपनी पहचान रखने वाली पारुल अब थ्रिलर फिल्म तू या मैं में नजर आएंगी। उन्होंने हाल ही में इस फिल्म और अपने किरदार को लेकर खुलकर बात की है और इसे अपने करियर का एक बेहद खास मौका बताया। फिल्म तू या मैं में पारुल गुलाटी के साथ आदर्श गौरव और शनाया कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय कर रहे हैं, जिनकी फिल्मों की पहचान भावनाओं, रिश्तों और गहराई से जुड़ी कहानियों के लिए रही है। इस फिल्म में पारुल लायरा नाम का किरदार निभा रही हैं, जो शनाया कपूर के किरदार की करीबी दोस्त और मैनेजर है। फिल्म का हिस्सा बनने पर पारुल ने कहा, आनंद एल राय का सिनेमा मुझे हमेशा से आकर्षित करता रहा है। फिल्म की कहानी नाटकीय होने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से शानदार है और दर्शकों को भीतर तक छू जाएगी।पारुल ने अपने किरदार को लेकर बताया, मेरा किरदार लायरा सिर्फ एक दोस्त नहीं है बल्कि एक ऐसा इंसान है जो हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती है, सही सवाल पूछती है, जरूरत पडने पर टोकती भी है और बिना शर्त समर्थन करती है। मैं इस किरदार को निभाकर बेहद खुश हूं और अभी भी इस एहसास में डूबी हुई हूं कि मुझे इतना अहम रोल निभाने का मौका मिला है।पारुल ने कहा, लायरा कोई साधारण या साइड कैरेक्टर नहीं है, बल्कि कहानी की भावनात्मक रीढ़ है। यह किरदार फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। मेरे लिए यह अनुभव इसलिए भी खास है क्योंकि मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहती थी जिनमें किरदारों की गहराई हो और कहानी दिल से जुड़ी हो। इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है।आनंद एल राय के साथ काम करने के अनुभव को लेकर पारुल गुलाटी ने कहा, एक कलाकार और एक क्रिएटर के तौर पर इससे बेहतर सहयोग शायद मुझे कभी नहीं मिल सकता था। आनंद एल राय की फिल्में वही सिनेमा हैं, जिनकी ओर मैं हमेशा खिंचती रही हूं। यह एक ऐसा दुर्लभ मौका है, जो जिंदगी में कम ही मिलता है, जहां बड़ी स्क्रीन की भव्यता के साथ-साथ कहानी में दिल और भावना दोनों मौजूद हों।पारुल गुलाटी ने फिल्म की पूरी टीम के प्रति आभार भी जताया। उन्होंने कहा, मैं मेकर्स की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे लायरा जैसा मजबूत किरदार सौंपा। मेरे लिए एक अनोखी थ्रिलर और क्रिएचर यूनिवर्स का हिस्सा बनना बेहद खास अनुभव है। मैं इस फिल्म को लेकर बहुत खुश, आभारी और उत्साहित हूं और चाहती हूं कि दर्शक इसे बड़े पर्दे पर जरूर देखें।

आलिया भट्ट की अमेजन प्राइम वीडियो के साथ अगली पेशकश, फिल्म डोंट बी शाय का ऐलान

आलिया भट्ट और शाहीन एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लेकर आ रही हैं, जिसका नाम है- डोंट बी शाय। यह प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्माण आलिया ने अपनी बहन शाहीन भट्ट के साथ मिलकर किया है। जानिए इस फिल्म में क्या खास है?

आलिया भट्ट और शाहीन एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लेकर आ रही हैं, जिसका नाम है- डोंट बी शाय है। इस फिल्म को इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंसन के तले बनाया गया है। आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आलिया कहती हैं- क्या कहानी में सब कुछ है। रोमांस है, दिल टूटता है, गाना है, लड़कियां, लड़के, और एक कछुआ भी...। दरअसल, यह एक ऐसी कहानी जिसके साथ आप बड़े होते हैं।

आलिया की मां सोनी राजदान ने कमेंट में लिखा, वाह, शानदार, बहुत बढ़िया किया आपने, फिल्म निर्माता अशर आस्कन ने लिखा, अब तक की सबसे प्यारी घोषणा, एक फैन ने लिखा, आपकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, दूसरे फैन ने लिखा, यह तो बेहद रोमांचक लग रहा है, इतने लंबे समय बाद ऐसी कोई फिल्म आई है, यह कमाल की होने वाली है।

आलिया भट्ट लव एंड वॉर में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया है। यह एक रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म है। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।

भूत पुलिस 2 के लिए निर्देशक प्रियदर्शन ने वूसली मोटी फीस, इस बार दिखेंगे नए चेहरे

सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम की हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस 2021 में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन पवन कृपलानी ने किया था जिसे लोगों ने ठीक-ठाक प्रतिक्रिया दी। अब इस फिल्म का सीक्वल चर्चा में है जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी प्रियदर्शन ने उठाई है। उन्हें हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि भूत पुलिस 2 के लिए के लिए प्रियदर्शन ने मोटी फीस वसूली है।रिपोर्ट के मुताबिक, भूत पुलिस 2 पर आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके निर्देशन के लिए प्रियदर्शन को चुना गया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि प्रियदर्शन इस सीक्वल का निर्देशन करने के लिए 21 करोड़ रुपये फीस ले रहे हैं। सूत्र ने आगे बताया कि पहली किस्त की तरह सीक्वल भी हॉरर-कॉमेडी जॉनर को बरकरार रखेगा लेकिन कास्टिंग में बड़ा बदलाव होगा। सैफ और अर्जुन की बजाए नई जोड़ी पर दांव लगेगा।सूत्र ने आगे कहा, विचार यह है कि एक नई जोड़ी के साथ इस फ्रैंचाइज को नया रूप दिया जाए। निर्माता 2 अभिनेताओं पर विचार कर रहे हैं। फिल्म की कास्टिंग प्रक्रिया और प्री-प्रोडक्शन का काम पूरा होने के बाद, शूटिंग इस साल के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है।

बॉक्स ऑफिस पर 9वें दिन भी बॉर्डर 2 ने की जमकर कमाई, श्मर्दानी 3 ने भी वीकएंड का उठाया फायदा, दूसरे दिन कलेक्शन में किया इजाफा

सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में चल रही हैं। इसमें मर्दानी 3, बॉर्डर 2 और मयसभा शामिल हैं। दूसरे दिन मर्दानी 3 को वीकएंड का फायदा मिला है। वहीं बॉर्डर 2 के कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। सिनेमाघरों में पहले से चल रही बॉर्डर 2 ने शनिवार को नई रिलीज हुई फिल्म मर्दानी 3 से ज्यादा कलेक्शन किया है। आइए जानते हैं कि मर्दानी 3, बॉर्डर 2 और मसयभा ने कितना कलेक्शन किया है।

सनी देओल की अगुआई वाली फिल्म बॉर्डर 2 को वीकएंड का फायदा मिला है। नौवें दिन इसने 17.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। पहले दिन इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपये और चौथे दिन सबसे ज्यादा 59 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। फिल्म ने अब तक 252.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। मर्दानी 3 की रिलीज से इस फिल्म पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है।

30 जनवरी को सिनेमाघरों में रानी मुखर्जी की अदाकारी वाली फिल्म मर्दानी 3 ने दस्तक दी। पहले दिन फिल्म का कलेक्शन 4 करोड़ रुपये रहा। दूसरे दिन फिल्म को वीकएंड का फायदा मिला और इसने 6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 10 करोड़ रुपये हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपये है। बजट के हिसाब से फिल्म का कलेक्शन औसत है।

30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म मयसभा-द हॉल ऑफ इल्यूजन की कमाई में इजाफा हुआ है। पहले दिन फिल्म ने 12 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन इसने 22 लाख रुपये का कलेक्शन किया है।

हिन्दी दैनिक जोखिम

सहसपुर ब्लॉक में वीबी-जी राम जी बिल पर हुई कार्यशाला आयोजित

देहरादून संवाददाता. प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सहसपुर ब्लॉक में आयोजित "विकसित भारत ख्र रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)" यानी वीबी-जी राम जी बिल-2025 पर आधारित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और स्थानीय लोगों से संवाद कर सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग द्वारा समूह की महिलाओं नि:शुल्क पौध भी वितरण किया।मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को लेकर निरंतर योजनाएं लागू की जाती रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना से शुरू होकर यह व्यवस्था 2006 में नरेगा और 2009 में मनरेगा के रूप में मजबूत हुई। अब वीबी-जी राम जी योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को 100 के बजाय 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना में निष्पक्ष वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सामान्य राज्यों के लिए 60:40 तथा हिमालयी व पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 का केंद्र-राज्य अनुपात तय किया गया है। साथ ही समयख्रबुवाई और कटाईख्रके दौरान राज्य सरकार वर्ष में 60 दिन ऐसे तय कर सकेगी, जब योजना के अंतर्गत कार्य नहीं कराया जाएगा, जिससे खेती के लिए पर्याप्त श्रमिक

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में रिटेनिंग वॉल (सुरक्षा दीवार) को अनुमन्य कार्यों में शामिल किया गया है।मंत्री जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा को समाप्त करने की अफवाहें निराधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में योजना को और अधिक सशक्त बनाया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्रीय बजट 2026-27 में 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना' की भी शुरुआत की जा रही है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने यह भी बताया कि कृषि के व्यस्त उपलब्ध रह सकें। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव को भी इस योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, कृषि एवं आजीविका संवध न को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार को और सशक्त करने के उद्देश्य से मनरेगा का बजट 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95,692 करोड़ रुपये कर दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों में उल्लेखनीय

धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया

- मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद प्राधिकरण तय करेगा सेलेब्स

देहरादून संवाददाता. उत्तराखंड सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रही है। नई व्यवस्था में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। विशेष सचिव डॉ पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा करते हुए इस वर्ष जुलाई से सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंब्रेला के नीचे लाने और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने की बात कही थी। डॉ पराग ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उक्त बोर्ड में प्रोफेसर विद्वान को मनोनीत किया गया है जोकि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी।इसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया है। डॉ पराग ने बताया कि इसमें डॉ सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष, प्रोफ राकेश जैन, डॉ सैय्यद अली हमीद,प्रो पेमा तेनजिन , डॉ एल्बा मेड्रिले, प्रोफेसर रोबिना अमन,प्रो गुरमीत सिंह,को सदस्य बनाया गया है साथ ही समाज सेवी राजेंद्र बिष्ट और सेवानिवृत अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट भी सदस्य होंगे। निदेशक महाविद्यालय शिक्षा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण भी सदस्य सूची में रहेंगे।

संक्षिप्त समाचार...

विधायक पुंडीर ने सुनी जनता दरबार लगाकर जनसमस्याएं

विकासनगर संवाददाता. सहसपुर के राघव विहार और अलकनंदा एनक्लेव में मंगलवार को विधायक सहदेव पुंडीर ने अधिकारियों के साथ जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने बिजली, पानी सड़क से संबंधित समस्याएं बताई। अधिकारियों को सभी समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए।

भूमि हस्तानांतरण के विरोध में छह को विरोध प्रदर्शन

विकासनगर संवाददाता. उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा यमुना घाटी प्रथम कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को निरीक्षण भवन डाकपत्थर में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारी नेताओं ने डाकपत्थर की भूमि हस्तानांतरण के विरोध में प्रदर्शन किया। निर्णय लिया कि छह फरवरी को डाकपत्थर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

वीबी-जी राम जी से ग्रामीण रोजगार को मिला नया विस्तार

विकासनगर संवाददाता. प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना ग्रामीण रोजगार को नया विस्तार देगा। यह बात उन्होंने सहसपुर ब्लॉक में आयोजित कार्यशाला में कही। इस दौरान उन्होंने किसानों और स्थानीय लोगों से संवाद कर सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति की विस्तृत जानकारी दी।

लोखंडी में बारिश, ओलावृष्टि से ठंड बढ़ी

विकासनगर संवाददाता. मंगलवार सुबह से चकराता में हल्के बादल छाए रहे। दोपहर बाद ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट बदली और लोखंडी में बारिश के बाद जमकर ओलावृष्टि हुई। जिससे चकराता और आसपास क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है।

हेल्थ ऑफिसर की हार्ट अटैक से मौत

विकासनगर संवाददाता. स्वास्थ्य केंद्र रायगी मे तैनात हेल्थ आफिसर की मंगलवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए विकासनगर भेजा है। रायगी में तैनात चिकित्सक डॉ.रवि कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 28 वर्ष पिछले एक साल से तैनात थे।

सड़कों पर क्रश बैरियर और ब्लैक स्पॉट होंगे चिह्ननित- मुन्ना सिंह चौहान

विकासनगर संवाददाता. विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्वानू मीनस मार्ग पर हुए हादसे पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा जल्द ही लोनिवि, एआरटीओ के साथ मिलकर सड़कों का निरीक्षण किया जाएगा। जहां भी क्रश बैरियर की आवश्यकता होगी और ब्लैक स्पॉट होंगे उन्हें चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल रोडवेज की बस खाई में गिरी, तीन की मौत, 33 घायल

विकासनगर संवाददाता. क्वानू-मीनस मार्ग पर मंगलवार सुबह सुदोई खड्ड के पास हिमाचल रोडवेज की बस सड़क से पचास मीटर नीचे खाई में गिर गई। दुर्घटना में दो महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि 33 यात्री घायल हो गए। घायलों को उपजिला चिकित्सालय विकासनगर, ग्राफिक एरा और लेहमन और पांवटा में भर्ती कराया गया है। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई रही है। छोटे वाहन को साइड देते समय सड़क का पुश्ता टूटने से यह हादसा हुआ।

उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड

- राज्य गठन के बाद पहली बार साल भर का आंकड़ा 6 करोड़ के पार

- हरिद्वार पहुंचे सर्वाधिक 3 करोड़ 42 लाख 49 हजार पर्यटक/तीर्थयात्री

देहरादून संवाददाता. पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लाई है। प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने नया कीर्तिमान बनाया है। वर्ष 2025 में छह करोड़ तीन लाख से अधिक पर्यटक उत्तराखण्ड आए हैं, जो राज्य गठन के बाद से अब तक की सर्वाधिक संख्या है। हरिद्वार में सबसे अधिक तीन करोड़ 42 लाख 49 हजार 380 पर्यटक/तीर्थयात्री पहुंचे हैं। जबकि देहरादून में 67 लाख 35 हजार 71 और टिहरी जनपद में 53 लाख 29 हजार 759 सैलानी आए हैं।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में पर्यटन को नई गति मिली है। पर्यटन विकास के लिए जहां कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, वहीं पर्यटन/तीर्थ स्थलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खास जोर दिया गया है। पर्यटकों/तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। धामी सरकार के इन प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में कुल 06 करोड़ 03 लाख 21 हजार 194 पर्यटक/तीर्थयात्री उत्तराखण्ड आए हैं। इनमें एक लाख 92 हजार 533 विदेशी सैलानी शामिल हैं। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद पहली बार पर्यटकों/तीर्थयात्रियों की संख्या छह करोड़ के पार पहुंची है। पूर्व के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो वर्ष 2021 में 2,00,18,115, 2022 में 5,39,81,338, 2023 में 5,96,36,601 और वर्ष 2024 में 5,95,50,277 पर्यटक/तीर्थयात्रियों ने उत्तराखण्ड का रुख किया है।पर्यटन उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। हमारी सरकार राज्य में पूरे वर्ष पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, ताकि पर्यटन कारोबार से जुड़े स्थानीय निवासियों और युवाओं को सालभर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। शीतकालीन यात्रा इसी की एक कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां गंगा जी के दर्शन को उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा की यात्रा पर आने के बाद राज्य में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिला है और बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखण्ड पहुंचे हैं। हमने पर्यटक सुविधाएं बढ़ाने के साथ उनकी सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखण्ड में पर्यटकों की बढ़ती संख्या हर वर्ष नया रिकॉर्ड बना रही है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक संजीव पंत द्वारा जेल रोड, हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखण्ड से प्रकाशित एवं चिराग पब्लिकेशन जेल रोड, हल्द्वानी नैनीताल से मुद्रित। सम्पादक - राजेश पंत
फोन नं0- 05946-254443 प्रसार प्रबंधकः वसीम अहमद , आर एन आई नं.: UTTHIN/2010/36647 email: jokhimhaldwani2013@gmail.com
ताज़ातरीन खबरों व सही जानकारी के साथ समाचार को विस्तार से पढ़ने के लिए लागआन करें हमारा newsportal:. jokhimnews.com